खबर संक्षेप

स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य आवंटित, अब बैंकों को समय पर देना होगा लोन

शहडोल। जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोडऩे के लिए प्रशासन ने एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के कुशल निर्देशन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत जिले की बैंक शाखाओं को शत-प्रतिशत लक्ष्य आवंटित कर दिए गए हैं।म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के भोपाल मुख्यालय से जारी निर्देशों के बाद स्थानीय स्तर पर इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। अब बैंक शाखाओं को पोर्टल के माध्यम से मिलने वाले ऑनलाइन लोन आवेदनों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करना होगा, ताकि तय समय-सीमा में युवाओं को अपनी खुद की राह चुनने का मौका मिल सके। इसके साथ ही, लोन लेने वाले युवाओं को ब्याज अनुदान और सीजीटीएमएसई गारंटी शुल्क का लाभ भी आसानी से पोर्टल के जरिए दिया जाएगा।

कैसे करें संपर्क

यदि आप भी इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने सपनों को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो विस्तृत जानकारी के लिए पुराने टेक्निकल स्कूल भवन, शहडोल स्थित मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के कार्यालय में जाकर या सीधे मोबाइल नंबर 9424955173 पर संपर्क कर सकते हैं। यह पहल जिले के जनजातीय युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मील का पत्थर साबित होगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया 3000 सोक पिट का निर्माण

शहडोल। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जल के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य निरंतर जन सहयोग से किए जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल बचाने, संरक्षित करने एवं जल का महत्व बताने हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अखिलेश मिश्रा ने बताया है कि कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में जल संरक्षण और भूमिगत जलस्तर रिचार्ज की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा एक सप्ताह के अंदर अपने स्वयं के व्यय से 3000 से अधिक सोक पिट का निर्माण किया गया। सोक पिट निर्माण के साथ ही कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी दैनिक गतिविधियों में जल संचयन एवं संरक्षण का संकल्प भी लिया।

वैदिक मंत्रोच्चार से शिवमय हुआ विश्वविद्यालय

शहडोल। पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय का परिसर उस समय पूरी तरह आध्यात्मिक और भक्तिमय माहौल में सराबोर हो उठा, जब विश्वविद्यालय में कर्मकांड डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रायोगिक परीक्षा का भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों ने पूरी वैदिक परंपरा के साथ सामूहिक रुद्राभिषेक और रुद्री का सस्वर पाठ किया, जिससे पूरा परिसर शिवमय हो गया।

कार्यक्रम की शुरुआत कुलगुरु प्रो. रामशंकर, कुलसचिव प्रो. आशीष तिवारी, विभागाध्यक्ष प्रो. विनोद शर्मा और छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. प्रमोद पाण्डेय द्वारा भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई। इस अवसर पर कुलगुरु प्रो. रामशंकर ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि कर्मकांड केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने माध्यम है।

कलेक्टर ने पुलिसिया जांच पर उठाए गंभीर सवाल

खडहुली जमीन विवाद: जनता को गुमराह न करें!

400 करोड़ का घोटाला या सिर्फ अफवाहों का बाजार

शहडोल। जिले के ब्योहारी तहसील के ग्राम खडहुली में कथित करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले को लेकर मचे सियासी और प्रशासनिक घमासान ने अब एक बेहद आक्रामक मोड़ ले लिया है। जिस मामले को कुछ तत्वों द्वारा 400 करोड़ रुपए का महाघोटाला बताकर सुर्खियां बटोरी जा रही थीं, प्रशासनिक जांच और मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के पन्नों ने उसकी हवा निकाल दी है। जिला प्रशासन ने अब इस पूरे प्रोपेगैंडा पर सीधी और सख्त चोट की है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने दोटूक लफ्जों में साफ कर दिया है कि बिना पूरी जांच और वैधानिक परीक्षण के, महज एकतरफा आरोपों के दम पर सनसनी फैलाना और जनता को गुमराह करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने सीधे पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव को पत्र लिखकर ब्योहारी थाना प्रभारी जिया उल हक की कार्यप्रणाली और उनकी जांच पर बेहद गंभीर और तीखे सवाल खड़े कर दिए। कलेक्टर ने अपने पत्र में साफ लिखा कि पुलिस द्वारा पेश किया गया आरोप पत्र पूरी तरह से एकतरफा और पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी ने बिना पर्याप्त साक्ष्यों और तथ्यों को परखे, सिर्फ शिकायतकर्ता को फायदा पहुंचाने के लिए यह पूरी पटकथा तैयार कर दी है।

संयुक्त कलेक्टर की जांच में क्लीन चिट

प्रशासनिक हलकों से आ रही खबरें बताती हैं कि इस मामले में पहले भी विस्तृत जांच की जा चुकी है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने स्पष्ट किया हमने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। पुलिस का आरोप पत्र पूरी तरह एकतरफा है। संयुक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय जांच में यह साफ हो चुका है कि इस भूमि मामले में न तो कोई घोटाला हुआ है और न ही किसी तथ्य को छिपाकर सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त की गई है। जब प्रशासनिक जांच में कोई आर्थिक क्षति या अवैध काम प्रमाणित ही नहीं हुआ, तो पुलिस की यह जल्दबाजी किस ओर इशारा करती है।

400 करोड़ का दावा या हवा-हवाई आंकड़ा

इस पूरे कथित घोटाले की सबसे

हास्यास्पद और चौंकाने वाली कड़ी इसका मूल्यांकन है। शिकायतकर्ता मुकेश मिश्रा से जब सवाल किया गया कि आखिर गांव की महज 10 एकड़ जमीन का मूल्य 200 से 400 करोड़ रुपए किस गणित के आधार पर तय कर दिया गया तो, उनका जवाब था कि यह आकलन क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त और बाजार मूल्य के आधार पर किया गया है, लेकिन जब सरकारी रिकॉर्ड और गाइडलाइन की हकीकत खंगाली गई, तो जमीन पर चल रहा यह दावों का खेल बेनकाब हो गया। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक, संबंधित भूमि की वास्तविक कीमत महज 10 से 12 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। अब प्रशासनिक गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है कि जिस जमीन की सरकारी कीमत चंद लाख रुपए है, उसे सैकड़ों करोड़ का बताकर किसके इशारे पर सनसनी फैलाई जा रही है, खडहुली जैसे शांत ग्रामीण इलाके में न तो कोई बड़ा औद्योगिक हब है और न ही कोई चमचमाती व्यावसायिक गतिविधि, फिर जमीन की कीमतों का यह फर्जी गुब्बारा क्यों फुलाया गया।

70 साल पुराने रिकॉर्ड की हकीकत

राजस्व विशेषज्ञों और प्रशासनिक जांच के मुताबिक, ग्राम खडहुली के सभी 16 आरजी खातों के सरकारी अभिलेखों के परीक्षण में कई चौंकाने वाले तथ्य आए हैं। मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के लागू होने के पहले से ही यह संशोधित भूमि निजी खातों में दर्ज चली आ रही है। पुराने रिकॉर्ड में निजी खातेदारों के नाम के आगे गैर हकदार शब्द जरूर दर्ज था, लेकिन साल 1982 से 1993 के बीच के दस्तावेजों में यह शब्द गायब था। इसके बाद साल 2014-15 में कुछ खातों में इसे फिर से जोड़ दिया गया। राजस्व नियमों के तहत अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को यह कानूनी अधिकार है कि यदि बिना किसी सक्षम आदेश या वैधानिक आधार के खसरे में चरनोई या गैर हकदार जैसी प्रविष्टियां जोड़ी गई हैं, तो वे उन्हें विलोपित (हटा) कर सकते हैं।

सनसनीखेज न बनाएं, तथ्यों पर करें बात

प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि संवेदनशील राजस्व मामलों को सियासी अखाड़ा या सनसनी का जरिया बनाने के बजाय तथ्यों के आईने में देखा जाना चाहिए। 70 साल पुराने उलझे हुए रिकॉड्र्स का पूरी तरह कानूनी और तकनीकी परीक्षण किए बिना किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना न सिर्फ जल्दबाजी होगी, बल्कि न्याय के सिद्धांतों का कत्ल होगा। फिलहाल, कलेक्टर के इस आक्रामक रुख के बाद पुलिसिया जांच और कथित समाजसेवियों के दावों पर कड़े सवालिया निशान लग गए हैं।

राजस्व मामलों के जानकारों का कहना है कि सिर्फ किसी जमीन पर गैर हकदार लिख देने से वह जमीन अपने आप सरकारी नहीं हो जाती। यदि किसी भूमि पर कोई परिवार दशकों (70 वर्षों से अधिक) से काबिज है, उसका नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है और वह नियमित रूप से सरकार को लगान चुका रहा है, तो उसे सीधे सरकारी घोषित करना कानूनन गलत और अन्यायपूर्ण है।

पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना हम सब का दायित्व है। आपने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों के लिए निकाय स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं। इसके साथ ही जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाया जाए। कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली पेयजल से संबंधित शिकायतों की जानकारी संबंधित क्षेत्र के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा नगरीय क्षेत्र के पेयजल प्रभारी को दी जाए। संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि 48 घंटे के भीतर शिकायत का निराकरण करें। इसके साथ ही पेयजल से संबंधित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के भी नियमित मानीटरिंग कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जिले में नए ट्यूबवेल खोदने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि किसी शासकीय विभाग द्वारा ट्यूबवेल खनन किया जाता है तो संबंधित एसडीएम को जानकारी दी जाए। आपने बताया कि राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को पीएचई विभाग के एसओआर के अनुसार पेयजल संरचनाओं की मरम्मत के अधिकार दिए गए हैं। प्रावधानों के अनुसार जहां पानी की समस्या है वहां ग्राम पंचायतें त्वरित समस्या का निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि जिन स्थानों में पेयजल समस्या है वहां जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। आपने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से भ्रमण में रहें तथा आगामी दिनों में पेयजल संकट वाले स्थानों का चिन्हांकन कर पूर्व से ही वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं। हैण्डपंपों की मरम्मत एवं राइजर पाईप बढ़ाने का कार्य त्वरित रूप से किया जाए। स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल की गुणवत्ता का सतत रूप से परीक्षण किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रो से आने वाली पेयजल समस्याओं पर की गई कार्यवाही की दैनिक जानकारी सीईओ जिला पंचायत को तथा नगरीय क्षेत्रों की शिकायतों पर की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी से कलेक्टर को अवगत कराएं।

विश्वविद्यालय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक सम्पन्न

शहडोल। कुलगुरु प्रो. रामशंकर ने पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरो की बैठक ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय डिजिटल युग का समय है, जहां सोशल मीडिया समाज की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि यदि सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ किया जाए तो यह समाज में जागरूकता, शिक्षा एवं प्रेरणा का प्रभावी माध्यम बन सकता है। कुलगुरु ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी प्रमुख मंच है। ऐसे में विश्वविद्यालय और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बीच समन्वय स्थापित कर युवाओं को रचनात्मक दिशा प्रदान की जा सकती है। उन्होंने विश्वविद्यालय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के एक स्थायी एवं योजनाबद्ध समूह के निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस पहल से विश्वविद्यालय की गतिविधियों, शोध, नवाचार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सामाजिक सरोकारों को व्यापक स्तर पर समाज तक पहुँचाया जा सकेगा। बैठक का उद्देश्य सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग, समाजोन्मुखी गतिविधियों के प्रसार तथा विश्वविद्यालय स्तर पर एक सशक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की दिशा में विचार-विमर्श करना था। बैठक में विश्वविद्यालय के डॉ. मुनीश नेगी, डॉ. सौरभ शिवा, डॉ. वंदना राम, डॉ. लोकेश साहू एवं डॉ. दिलीप तिवारी,मनीष तिवारी सहित सोषल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स उपस्थित रहे।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मृत पाये गए नर बाघ का हुआ पोस्ट मॉर्टम

मृत्यु कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर के कारण होने की आशंका

जांच के लिए एडवांस लैब्स में भेजे गए नमूने

उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया अंतर्गत पनपथा बफर क्षेत्र के ग्राम खेरवा टोला में 24 मई 2026 को मृत पाए गए नर बाघ का पोस्टमॉर्टम 25 मई 2026 को किया गया। पोस्टमॉर्टम 3 वन्यजीव चिकित्सकों के पैनल और 2 आमंत्रित विशेषज्ञों की उपस्थिति में हुआ।

पोस्टमॉर्टम में बाघ के सभी अंगों का गहन परीक्षण किया गया और आवश्यक नमूने संग्रहित किए गए। पोस्टमॉर्टम में एकत्रित नमूनों को बीमारी, अन्य आंतरिक रोगों, तनाव अथवा विषाक्तता जैसी संभावनाओं की जांच के लिए मानक प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। पोस्टमॉर्टम में डायरेक्टर, स्टेट वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक हेडक्वार्टर (एसडब्ल्यूएफएच) जबलपुर, क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तथा एनटीसीए के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमॉर्टम के बाद क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एवं एनटीसीए प्रतिनिधि की उपस्थिति में 25 मई 2026 को जबलपुर में बाघ का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। पोस्टमॉर्टम में चिकित्सकों और विशेषज्ञों के पैनल ने पाया कि मृत नर बाघ का स्वास्थ्य अत्यंत खराब था। उसकी मांसपेशियां पीली एवं सूखी थीं, पाचन तंत्र खाली था और त्वचा खुरदरी और बेजान हो चुकी थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि ट्रैंक्विलाइजर डार्ट दाहिने कंधे पर लगा था, जहां रक्तस्राव नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डार्ट बाघ की मृत्यु के बाद लगाया गया था। शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में 'कंजेस्टिव एवं हेमरेजिक' परिवर्तन पाए गए, जो कमजोर रक्त संचार के संकेतक हैं। पोस्टमॉर्टम करने वाले विशेषज्ञों के अनुसार बाघ की मृत्यु कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर के कारण हुई होगी।

लोकगीत एवं लोक नृत्य के माध्यम से जल संरक्षण का दिया गया संदेश

शहडोल। जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य उपहार है, जो समस्त जीव-जगत के अस्तित्व का आधार है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। इसलिए हमें जल की एक-एक बूंद के महत्व को समझना होगा और इसके संरक्षण के लिए जागरूक होना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जल के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नवीन खेत तालाब, बोरी बंधान, रैन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे अन्य कार्य किये जा रहे है। इन कार्यो से वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा के जल का संचयन होगा और धरा के जल स्तर में वृद्वि होगी वहीं स्थानीय लोगो के लिए फसल सिंचाई जैसे अन्य कार्यों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पड़मनिया खुर्द में जल के सरंक्षण एवं संवर्धन की अलख जगाने के लिए स्थानीय कलाकारो द्वारा लोकगीत एवं लोकनृत्य किया गया एवं जनमानस को जल की एक-एक बूंद सहेजने हेतु जल चौपाल

कार्यक्रम आयोजित किया गया। जल चौपाल में उपस्थिति अधिकारियो द्वारा बताया गया कि जल के संवर्धन एवं संरक्षण के प्रति सचेत होना होगा, हमें आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए अभी से जल का बचाना होगा। इस अवसर पर प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोहागपुर श्री गैलेक्सी नागपुरे, सरपंच श्रीमती कमलेशिया बैगा, उपसरपंच अनिल साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहें।

बेटियों की सुरक्षा और स्वावलंबन से चमकेगा शहडोल का पर्यटन

ज्ञानोदय स्कूल में जन पैरवी कार्यक्रम आयोजित

शहडोल। हमारे जिले के पर्यटन स्थलों को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित, सहज और अनुकूल बनाने की दिशा में एक शानदार और सकारात्मक पहल की गई है। पुलिस लाइन स्थित ज्ञानोदय हिंदी मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में वोकेशनल स्पोर्ट्स के दौरान एक विशेष जन पैरवी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (भोपाल) द्वारा संचालित महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के तहत इंडियन ग्रामीण सर्विसेज द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्ञानोदय शिक्षा समिति के डायरेक्टर अजय सिंह रहे। इस मौके पर समाज और पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर बेहद प्रेरक चर्चा हुई।

1,000 बेटियों को मिला आत्मरक्षा का कवच

आईजीएस के शहडोल संकुल समन्वयक सुशील कुमार पाण्डेय ने बताया कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदेश के 50 पर्यटन स्थलों (20 क्लस्टर्स) में सफलतापूर्वक चल रही है। इसके तहत पर्यटन स्थलों के पास स्थित स्कूल-कॉलेजों की छात्राओं को 60 दिनों का आत्मरक्षा प्रशिक्षण देकर उनके भीतर गजब का आत्मविश्वास भरा जा रहा है। शहडोल जिले में अब तक 1,000 छात्राओं को कराटे और लाठी संचालन का कड़ा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कार्यक्रम के दौरान ऐसी ही प्रतिभावान छात्राओं को मुख्य अतिथियों द्वारा ट्रैक सूट और सर्टिफिकेट वितरित कर प्रोत्साहित किया गया।

300 से अधिक महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

परियोजना का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि रोजगार भी दे रही है। पर्यटन स्थलों के आसपास रहने वाली स्थानीय युवतियों और महिलाओं को विभिन्न भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिले में अब तक 300 से अधिक महिलाओं को पर्यटन अनुकूल ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार और आजीविका से जोड़ा जा चुका है, जिससे अब हमारे पर्यटन स्थलों पर महिला सेवा प्रदाताओं की गरिमामयी मौजूदगी बढ़ रही है।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

इस गरिमामयी आयोजन में महिला डेस्क की पुलिस इंस्पेक्टर श्रीमती नेहा उइके, आरक्षक सुरजीत सिंह, जिला शालेय विज्ञान प्रभारी संतोष कुमार मिश्रा, स्टेट कराटे कोच श्री प्रमोद विश्वकर्मा, कराटे प्रशिक्षिका शिवानी नामदेव, टूर एंड ट्रैवल्स मैनेजर सुचित सिंह, टूरिस्ट फेसिलेटर श्री सुमित दत्ता, समाजसेवी आई. जे. सिंह और वोकेशनल स्पोर्ट्स स्टाफ सहित करीब 60 गणमान्य नागरिक और प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे।

नहाने गए युवक की गहरे पानी में डूबने से दर्दनाक मौत

पिकनिक स्पॉट पर कब जागेगा प्रशासन

शहडोल। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत पाने की चाहत एक बार फिर एक हंसते-खेलते परिवार के लिए जिंदगी भर का मातम बन गई। स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोन टोला डैम (दियापीपर) में नहाने गया एक युवक गहरे पानी की बेरहम लहरों का शिकार हो गया। मृतक की शिनाख्त कोटम जानकी मंदिर के सामने रहने वाले अंशु बर्मन पिता रामू बर्मन के रूप में हुई है। इस कलेजा चीर देने वाले हादसे के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

चिलचिलाती धूप में दोस्तों संग गया था नहाने

दिल दहला देने वाली यह घटना बीते कल दोपहर करीब 2 बजे की है। चिलचिलाती धूप से परेशान होकर अंशु अपने 3-4 दोस्तों के साथ घूमने और नहाने के लिए सोन टोला डैम गया हुआ था। पानी

में उतरकर सभी दोस्त मस्ती कर रहे थे, लेकिन इसी बीच लापरवाही और बदइंतजामी का काल मंडराने लगा। नहाते-नहाते अंशु अचानक गहरे पानी की चपेट में आ गया और डूबने लगा। अंशु को मौत के मुंह में जाते देख उसके साथियों ने चीख-पुकार मचाई और उसे बचाने की नाकाम कोशिश भी की, लेकिन बांध की गहराई के आगे उनकी एक न चली और देखते ही देखते अंशु गहरे पानी में विलीन हो गया।

मशक्कत के बाद निकाला शव

हादसे की खबर मिलते ही गोहपारू थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर दौड़ी। स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से डैम के खौफनाक पानी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घंटों की भारी मशक्कत के बाद आखिरकार अंशु के बेजान शरीर को पानी से बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आखिर कब तक जिले के ऐसे खतरनाक और असुरक्षित जलाशय युवाओं के लिए डेथ वारंट बनते रहेंगे? प्रशासन ने एक बार फिर रटा-रटाया बयान जारी कर लोगों से गहरे पानी में न उतरने की अपील की है, लेकिन सवाल यह है कि इन डेंजर जोन वाले बांधों और पिकनिक स्पॉट्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और चेतावनी बोर्ड लगाने की जहमत जिम्मेदार क्यों नहीं उठाते।

साल बदला, पर नहीं बदली 11 लाख की सडक़ की सूरत

ग्राम पंचायत लखनौटी बनी भ्रष्टाचार का गढ़

कागजों पर बही विकास की गंगा, जमीन पर सिर्फ 100 मीटर का छलावा, सरपंच-सचिव और उपयंत्री की त्रिमूर्ति ने खजाने में लगाई सेंध, रसूखदार सरपंच पति चला रहे समानांतर सरकार

मानपुर। सूबे की सरकार एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण के बड़े-बड़े दावे करते नहीं थकती, वहीं जमीनी हकीकत इसके उलट बेहद शर्मनाक है। जनपद पंचायत मानपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लखनौटी इसका जीता-जागता उदाहरण बन चुकी है। यहां महिला सशक्तिकरण के नाम पर चुनी गईं महिला सरपंच महज एक रबर स्टैंप बनकर रह गई हैं, जबकि पंचायत की असली कमान और मलाई काटने का काम उनके सरपंच पति मजे से कर रहे हैं। इस पतिराज और अधिकारियों की जुगलबंदी का नतीजा यह है कि आज लखनौटी पंचायत भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह डूब चुकी है।

साल बीता, पर अधूरी है 11.20 लाख की सडक़

मामला लखनौटी के उर्दना का है, जहां सुनील उपाध्याय के घर से लेकर शिवकुमार उपाध्याय के घर तक 11 लाख 20 हजार रुपये की लागत से सीसी रोड का निर्माण होना था। विडंबना देखिए कि इस काम को शुरू हुए एक साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ठेकेदारी और भ्रष्टाचार के गठजोड़ ने जनता को महज 100 मीटर की सडक़ थमाकर पल्ला झाड़ लिया। बाकी के हिस्से में सिर्फ बेस डालकर छोड़ दिया गया है, जो आज पंचायत के दावों की पोल खोल रहा है।

अंधेरे में रखने की सोची-समझी साजिश

सरकारी नियमों के मुताबिक किसी भी निर्माण कार्य के शुरू होने से पहले वहां निर्माण एजेंसी का बोर्ड लगाना अनिवार्य है, ताकि जनता को लागत, मद और एजेंसी की सही जानकारी मिल सके, लेकिन लखनौटी में नियम-कायदों को ताक पर रख दिया गया। आज तक यहां कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया। यह इस बात का सीधा सबूत है कि जनपद पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत के आला हुक्मरान इस महाघोटाले में शामिल हैं और वे सच को जनता की नजरों से छुपाना चाहते हैं।

निकाल लिए 3.90 लाख रुपये

जमीन पर काम भले ही दम तोड़ चुका हो, लेकिन कागजों पर सरकारी राशि हड़पने का खेल पूरी रफ्तार से चला। अब तक इस अधूरे निर्माण कार्य के नाम पर 3 लाख 90 हजार रुपये की राशि आहरित की जा चुकी है। सरकारी खजाने में सेंधमारी की बानगी इन बिलों से साफ देखी जा सकती है। पहला सीमेंट बिल 18 अगस्त 2025 को 600 बोरी सीमेंट, 320 रुपये की दर से कुल 1,92,000 रुपये। दूसरा सीमेंट बिल (12 अगस्त2025) को 400 बोरी सीमेंट, 320 रुपये की दर से कुल 1,28,000 रुपये। बिना किसी रॉयल्टी के 35 ट्रॉली रेत, 2000 रुपये की दर से कुल 70,000 रुपये का भुगतान। जब 60 हजार से ज्यादा की रेत और लाखों की सीमेंट कागजों खप चुकी है, तो फिर जमीन पर काम शून्य क्यों है? क्या यह राशि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई?

तकनीकी नियमों का मखौल

इंजीनियरिंग के बुनियादी नियमों को ताक पर रखकर उपयंत्री की शह पर इस सडक़ का निर्माण किया गया। गाइडलाइन कहती है कि सीसी रोड से पहले सडक़ की खुदाई अनिवार्य है, लेकिन यहां बिना खुदाई किए ही सीधे मिट्टी के ऊपर बेस डाल दिया गया। यह घटिया निर्माण इस बात की तस्दीक करता है कि उपयंत्री ने सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में इस भ्रष्टाचार पर अपनी आंखें मूंद लीं।

रातों-रात रेत की चोरी और त्रिमूर्ति की जेबें गर्म

इस सडक़ में अवैध और चोरी की रेत का धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बिना रॉयल्टी वाले लोकल ट्रैक्टर रातों-रात यहां रेत गिरा जाते थे। इस अवैध रेत और फर्जी बिलों के सहारे शासन के पैसों का सरेआम दुरुपयोग किया गया। लखनौटी पंचायत की इस त्रिमूर्ति सरपंच (पति), सचिव और उपयंत्री ने मिलकर सरकारी राशि को विकास कार्यों में लगाने के बजाय अपनी जेबें भरने का जरिया बना लिया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

सुरक्षित माहवारी प्रबंधन से स्वस्थ और सशक्त बनेगी किशोरियां: कलेक्टर

किशोर स्वास्थ्य एवं माहवारी स्वच्छता पर विशेष कार्यक्रम आयोजित

उमरिया। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता माहवारी दिवस के अवसर पर किशोर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित माहवारी प्रबंधन विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं में माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना तथा सुरक्षित एवं सम्मानजनक माहवारी प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने कहा कि आज भी महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं, जिन पर समाज में खुलकर चर्चा नहीं हो पाती। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन भी ऐसा ही एक विषय है, जिसका सीधा संबंध किशोरियों के शारीरिक,मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित माहवारी प्रबंधन न केवल संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव करता है, बल्कि किशोरियों के आत्मविश्वास,गरिमा और जीवन की गुणवत्ता को भी सुदृढ़ बनाता है।

कलेक्टर ने कहा कि समाज में माहवारी को लेकर सकारात्मक संवाद और जागरूकता बढ़ाना समय की आवश्यकता है,ताकि किशोरियां बिना किसी संकोच के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी और सुविधाएं प्राप्त कर सकें। उन्होंने सभी से माहवारी स्वच्छता को स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़े विषय के रूप में देखने तथा जागरूकता अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान ग्राम स्तर पर किशोर स्वास्थ्य एवं जनजागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले साथिया सदस्यों को सम्मानित किया गया। प्रोत्साहन स्वरूप शील्ड प्रदान कर ग्राम दुब्बार की तान्या राय, ग्राम बडग़ांव के साथिया किशन सोनी तथा उमंग स्वास्थ्य केंद्र में किशोर स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहे राकेश चौधरी को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. व्ही.एस. चंदेल, जिला किशोर स्वास्थ्य समन्वयक बुधराम राहंगडाले, डॉ. हर्षा पाटील, सीपीएचसी साथिया प्रशिक्षक प्रकाश असाटी सहित बड़ी संख्या में साथिया सदस्य एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम

स्वर्गीय विनायक दामोदर सावरकर की जयंती समारोह संपन्न

उमरिया। मेरा युवा भारत केंद्र उमरिया (मध्य प्रदेश) में कक्षा छठवीं से स्नातक के छात्र छात्राओं के साथ स्वर्गीय श्री विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मेरा युवा भारत केंद्र के जिला युवा अधिकारी उमाशंकर त्रिवेदी के निर्देशन में संपन्न हुआ । कार्यक्रम में श्री सावरकर की जीवन गाथा एवं देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में शामिल सभी युवा छात्र-छात्राओं ने भी वीर सावरकर जी एवं स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में अपने विचार रखे। कुछ युवा प्रतिभागियों ने कविता पाठ किया। अंत में सभी युवा प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वे माय भारत केंद्र के साथ जुड़कर अपने व्यक्तित्व, परिवार गांव समाज एवं जिले के विकास के लिए लगातार योगदान देते रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित सुनील सराठे, मेंटर जन अभियान परिषद इंदौर, माय भारत के वॉलंटियर आकाश बर्मन,काजल बर्मन, शिव प्रताप पाल,अरविंद यादव आदि शामिल रहे।

2 जून को डायरेक्ट एजेंट चयन हेतु वाक इन इंटरव्यू

उमरिया। अधीक्षक डाकघर शहडोल ने बताया कि डाकघर शहडोल संभाग शहडोल हेतु डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के व्यवसाय अर्जन हेतु डायरेक्ट एजेंट का चयन किया जाना है । जिसके लिए साक्षात्कार वाक इन इंटरव्यू का आयोजन 2 जून को दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक किया गया है ।अर्हताएं पूर्ण करने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन तथा बायोडाटा लेकर उक्त समयावधि में कार्यालय अधीक्षक डाक घर शहडोल संभाग प्रधान डाकघर परिसर में निर्धारित समय में उपस्थित होवे। उन्होंने बताया कि अर्हताएं शैक्षणिक योग्यता 10 वीं पास या समकक्ष राज्यध्केंद्रीय बोर्ड, आयु 18 वर्ष से अधिक,आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड,पैन कार्ड, 10वी की मार्कशीट एवं दो पासपोर्ट साइज की फोटो आवश्यक हैं। चयनित उम्मीदवारों को उनके व्दारा किए गए कार्य के आधार पर इंसेटिव प्रदान किया जाएगा । अधिक जानकारी के लिए 07652-240369 एवं 70009844490 पर संपर्क किया जा सकता है।

3 जून को डीएलआरसी एवं डीएलसीसी की बैठक

उमरिया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की मार्च 2026 तिमाही कि जिला स्तरीय समीक्षा (डीएलआरसी) एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक का आयोजन 3 जून 2026 को अपरान्ह क्रमशः 4 बजे एवं 5 बजे से कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय कि अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया है ।

बैठक में जिला सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की दिसम्बर 2025 तिमाही बैठक का कार्यवाही विवरणी,जमा एवं अग्रिम अनुपात तथा बैंकिंग पैरामीटर की समीक्षा , वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी) के प्रारूप पर चर्चा, जिले में एग्री क्लिनिक एवं एग्री-बिजनेस सेंटर योजना की समीक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विस्तृत चर्चा, सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई शिकायतों की समीक्षा, गैर निष्पादन सम्पत्तियाँ की समीक्षा एवं सुधार हेतु कार्ययोजना आरसीसी की समीक्षा,प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के इन्ट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम घटक अंतर्गत ईडब्ल्यूएस,एलआईजी,एम आई जी वर्ग के पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने संबंधी,एसबीआई आरसेटी उमरिया की समीक्षा,विभिन्न शासकीय योजनाओं की विभागवार अद्यतन प्रगति की समीक्षा, वित्तीय साक्षरता अभियान एवं प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को ग्रामीण शाखाओं के द्वारा शिविर आयोजन की समीक्षा,अनक्लेम्ड डिपोजिट के रिफंड की योजना एवं आरई केवायसी पर चर्चा सहित अन्य विषयो पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सर्व संबंधितों से उपस्थिति की अपेक्षा की गई है।

कोयला परिवहन से जर्जर हुई सड़क, धूल बन रही लोगों की परेशानी

धूल बन रही लोगों की परेशानी, गड्ढों से हो रही दुर्घटना, धूल से लोग हो रहे बीमारी के शिकार

हरिभूमि न्यूजकोतमा। आमाडांड से भालूमाड़ा तक पहुंचने के लिए बनी 15 किलोमीटर की सड़क जर्जर हो चली है। आमाडांड से गोबिंदा की ओर जाने वाला मार्ग कोयला परिवहन से पूरी तरह से टूटा व गड्ढायुक्त सडक़ में तब्दील हो गया है। जिस वजह से इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आये दिन दुर्घटना घटित हो रहा है बताया जाता है कि आमाडांड से गोबिंदा कालरी भालूमाड़ा की ओर जाने वाला लगभग 15 किलोमीटर लंबा यह मार्ग लंबे समय से जर्जर हालत में है। जिसकी मरम्मत पर कॉलरी प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए स्थानीय लोगों ने पूर्व में कॉलरी प्रबंधन तक शिकायत दर्ज कर मरम्मत की अपील की थी। परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों को आवागमन में असुविधाएं हो रही है।

धूल डस्ट से परेशान राहगीर

लंबे समय से इस मार्ग पर कोयला वाहनों के परिवहन की वजह से यह मार्ग जर्जर हो चुका है, जिसमें वाहनों के गुजरते ही धूल की गुबार आसपास के स्थानों पर हावी हो जाता है। इस दौरान सामने से आने वाले वाहनों को भी डस्ट के कारण दिक्कते आती है। लेकिन दूसरी ओर कॉलरी पानी का छिडक़ाव भी नहीं करा पा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस जर्जर सडक़ के निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसके बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है जिसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। आमाडांड से गोबिंदा साइडिंग तक जाने वाले मार्ग पर धूल उड़ने से राहगीर परेशान हैं। लोगों की यात्रा में धूल बाधक बन रही है। उड़ती धूल राहगीर की आंखों में पड़ जा रही है। धूल के कारण लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। आमाडांड से मझौली, बेलहा, पयारी, भालूमाड़ा, गोबिंदा साइडिंग तक जानेवाली सडक में बड़े बड़े गढ्ढे हो गये है। जिसके कारण दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कई बार गढ्ढो के कारण दो पहिया वाहन चालक चोटिल भी हो चुके हैं। यहां तक की कई बड़ी दुर्घटना भी घटित हो चुकी है जिसमें जान भी जा चुकी है।

पड़ी गिट्टी से परेशानी

इस सड़क पर कालरी प्रबंधन के द्वारा सड़क के बीचों बीच गिट्टी बिछा दी गई थी जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। सड़क पर गिट्टियां डालकर उसे रोलिग नहीं किया गया है पानी न डाले जाने से धूल उड़ रही है, जिससे लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। राहगीरों को सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब बड़े वाहन गुजरते हैं। बड़े वाहनों के पीछे चल रहे लोगों को धूल से कुछ दिखाई नहीं देता है। इससे सामने से आने वाले लोग भी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते। धूल के चलते लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं।

इन लोगों की आंखों में धूल के कण चले जा रहे हैं, जिससे दिखाई देने में समस्या हो रही है। कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। इसी रास्ते से स्कूली बच्चे भी आते जाते हैं। उनको भी परेशानी उठानी पड़ती है। लोगों ने कहा कि मार्ग पर पानी न डाले जाने से धूल उड़ रही है। इससे राहगीरों के साथ-साथ आसपास रह रहे लोगों को भी परेशानी हो रही है। सड़क किनारे बसे लोगों के घर धूल से पटे जा रहे हैं। दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानों की सफाई दिन में कई बार करनी पड़ रही है। जिम्मेदार इससे अनजान हैं।

मंत्री ने लिखा पत्र

मध्यप्रदेश शासन के लघु उद्योग कुटीर मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमुना कोतमा क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि आमाडांड से गोविंदा साईडिंग की तरफ जानें वाली सड़क जो कि कई ग्रामो को जोड़ती है, कम्पनी एवं कम्पनी ठेकेदारों के द्वारा चलाये जा रहे परिवहन के कारण सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है जो चलने योग्य नहीं है आए दिन दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। पूर्व में भी मेरे द्वारा कई बार मौखिक रूप से सड़क मरम्मतीकरण के निर्देश दिये गये है किन्तु आज तक कम्पनी प्रबंधन द्वारा उक्त निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। जिस कारण ग्रामीणजनों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। उपरोक्त सड़क का मरम्मतीकरण आगामी 1 माह के अन्दर कराये जानें की तत्काल समुचित कार्यवाही करें अन्यथा ग्रामीणों द्वारा आपका कोल परिवहन बन्द कराये जानें की संभावना है तथा भविष्य में होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए कंपनी प्रबंधन पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

प्रिंट रेट से अधिक शराब बिक्री और कथित पैकारी पर उठे सवाल, जांच की मांग तेज

हरिभूमि न्यूज बदरा/जमुना। श्रमिक नगर सहित आसपास के कई क्षेत्रों में संचालित शराब दुकानों की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। क्षेत्रवासियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ दुकानों में शराब प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर बेची जा रही है, जबकि कथित रूप से पैकारी व्यवस्था के माध्यम से भी शराब की बिक्री किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इन आरोपों के बाद आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। श्रमिक नगर के अलावा छुलहा, राजनगर, कोतमा एवं आसपास के अन्य क्षेत्रों से भी इसी प्रकार की शिकायतें सामने आने की चर्चा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ स्थानों पर निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूली जा रही है, जबकि कथित रूप से पैकारी के माध्यम से शराब की उपलब्धता भी बनी हुई है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के चलते लोगों ने मामले की गंभीर जांच की मांग उठाई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शराब खरीदने आने वाले उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली जा रही है। वहीं कई स्थानों पर दुकान के बाहर और मोहल्लों तक शराब पहुंचाए जाने की चर्चाएं भी आम हैं। लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो अवैध बिक्री और ओवररेटिंग जैसी गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। क्षेत्र के सामाजिक संगठनों एवं जागरूक

नागरिकों ने आबकारी विभाग और जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि शराब दुकानों की नियमित निगरानी, बिल जांच और स्टॉक सत्यापन कराया जाए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जनहित में व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। फिलहाल पूरे मामले में प्रशासनिक जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। मामले में जिला आबकारी अधिकारी अनूपपुर का पक्ष जानने के लिए दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनसे संपर्क नहीं हो सका। फोन पर घंटी जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

खबर संक्षेप

30000 पदों के सरेंडर के विरोध में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ का विशाल धरना-प्रदर्शन

शहडोल। रेलवे बोर्ड द्वारा 30000 पदों को सरेंडर किए जाने एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ आज बिलासपुर जोन द्वारा जी.एम. कार्यालय, बिलासपुर के समक्ष विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों, पदाधिकारियों एवं शाखा प्रतिनिधियों ने भाग लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जोनल अध्यक्ष कमलेश सिंह के द्वारा किया गया, मंच का संचालन जोनल कार्यवाहक अध्यक्ष विवेकानंद चंद्रा द्वारा किया गया कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री संतोष पटेल शामिल हुए एवं जोनल सलाहकार निमई बनर्जी व कार्यकारी महामंत्री बसंत महापात्रा की उपस्थिति रही । साथ ही साथ जोनल पदाधिकारियों में जोनल कोषाध्यक्ष अभिषेक रेड्डी, जोनल उपाध्यक्ष धानुक साहू, राजेश्वर नागपुरे एवं जोनल सहायक महामंत्री नूतन वर्मा, जोनल कार्यकारिणी सदस्य अनुज विश्वकर्मा, धर्मा राव, आर के पटेल, श्रीधर राव एवं मंडल से बिलासपुर मंडल अध्यक्ष राकेश साहू मंडल सचिव बिलासपुर प्रोम्पी सिंह एवं रायपुर मंडल से मंडल अध्यक्ष टाटा बाबू राव, मंडल सचिव सूरज देवांगन एवं रायपुर मंडल से मंडल अध्यक्ष सुशील सोनबेर, मंत्री डेरहा राम वर्मा एवं नागपुर मंडल से मंडल सचिव ध्रुव शर्मा की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में भारी संख्या में सभी ब्रांच के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए जिनमें ईश्वर लाल जांघेल, अंकित शुक्ला, अजय सिंह राठौर, नीतीश राय चौधरी, मनोज साहू, भागवत राठौर , वकील तिवारी, थानू राठौर, अनिल शर्मा, सन्नी कुमार , मंटू कुमार, गोविंद कौशिक, संजय यादव, शैलेश उपाध्याय, राम सिंह, आर के रवानी, संजय सिंह, पवन कुमार अनु दत्त, दीनानाथ, अभय राज, अमन राज, रणधीर कुमार, कुंदन कुमार, लेखराम साहू, चोला विजय साहू, पी शेम शेखर , उज्जवल दाश महंत, विक्रम कुमार रस्तोगी, आर के रवानी, एवं अन्य शामिल रहे ।धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ने कहा कि एक ओर भारतीय रेल में ट्रेनों की संख्या, कार्यभार एवं यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों के पद समाप्त किए जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ रहा है तथा रेलवे की सुरक्षा एवं कार्य व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। वक्ताओं ने कहा कि रेलवे केवल मशीनों से नहीं बल्कि कर्मचारियों की मेहनत, अनुभव एवं समर्पण से चलती है। यदि लगातार पद समाप्त किए जाते रहे तो इसका सीधा असर रेल संचालन एवं सुरक्षा पर पड़ेगा। संगठन ने मांग की कि सरेंडर किए गए पदों को तत्काल बहाल किया जाए तथा रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए।

आजाद चौक पर लोगों में नाराजगी

लाखों खर्च फिर भी बंद पड़ा मिस्ट सिस्टम: 40 डिग्री की झुलसाती गर्मी में राहत देने वाली व्यवस्था बनी शोपीस

धनपुरी।

ग्रीष्म ऋतु की झुलसा देने वाली गर्मी और 40 डिग्री तक पहुंच चुके तापमान के बीच नगर पालिका धनपुरी द्वारा नगरवासियों को राहत देने के लिए शुरू किया गया वॉटर स्प्रे मिस्ट सिस्टम अब सवालों के घेरे में आ गया है। नगर के हृदय स्थल आजाद चौक एवं नेहरू कॉलेज तिराहे पर पहली बार लगाए गए इस आधुनिक सिस्टम से शुरुआती दिनों में लोगों को काफी राहत मिली, लेकिन अब यह कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है।नगरपालिका ने बढ़ते तापमान और गिरती वायु गुणवत्ता को देखते हुए यह व्यवस्था शुरू की थी। मिस्ट सिस्टम के माध्यम से वातावरण में ठंडी फुहारें छोड़ी जा रही थीं, जिससे न केवल गर्मी से राहत मिल रही थी बल्कि उड़ने वाली धूल भी नियंत्रित हो रही थी।

राहगीर, वाहन चालक और बाजार आने वाले लोग कुछ देर रुककर गर्मी से राहत महसूस कर रहे थे।शुरुआत में नगरवासियों ने नगरपालिका और सीएमओ पूजा बुनकर की इस पहल की जमकर सराहना की थी। लोगों का कहना था कि पहली बार नगर में भीषण गर्मी को देखते हुए इस तरह की आधुनिक व्यवस्था देखने को मिली। सुबह और शाम के समय आजाद चौक पर लोगों की भीड़ लग रही थी और लोग ठंडी फुहारों के बीच सुकून महसूस कर रहे थे।लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। कई दिनों से बंद पड़े मिस्ट सिस्टम को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च कर लगाया गया सिस्टम यदि कुछ ही दिनों में बंद हो जाए तो इसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। नगर में अब "चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात" वाली कहावत चर्चा का विषय बनी हुई है।लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी के समय जिस व्यवस्था की सबसे ज्यादा जरूरत है, वही व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। यदि नगरपालिका नियमित मॉनिटरिंग और रखरखाव सुनिश्चित नहीं कर पा रही है तो ऐसी योजनाओं का लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचेगा।जानकारी के अनुसार नगरपालिका द्वारा तीन नंबर कॉम्प्लेक्स एवं मॉडल रोड डिवाइडर क्षेत्र में भी इसी तरह के मिस्ट सिस्टम लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि नगरवासियों का कहना है कि पहले से लगे सिस्टम को सुचारु रूप से चालू रखना ज्यादा जरूरी है।वहीं जागरूक नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से भी अपील की है कि आजाद चौक फव्वारा क्षेत्र के आसपास अव्यवस्थित पार्किंग पर नियंत्रण किया जाए। लोगों का कहना है कि यदि मिस्ट सिस्टम नियमित रूप से संचालित हो और यातायात व्यवस्था सुधर जाए तो आजाद चौक की सुंदरता और आकर्षण दोनों बढ़ सकते हैं।

रामपुर में फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, विस्थापन, रोजगार और पुनर्वास को लेकर उबल पड़ा जनाक्रोश, बढ़ती हलचल के बीच GM बी.के. जेना को गांव पहुंचकर करनी पड़ी मैराथन

धनपुरी। एसईसीएल सोहागपुर एरिया अंतर्गत रामपुर ओपन कास्ट क्षेत्र इन दिनों विस्थापन, पुनर्वास और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर जबरदस्त उबाल में है। वर्षों से दबे आक्रोश ने अब खुलकर सामने आना शुरू कर दिया है। किसानों, प्रभावित परिवारों और बेरोजगार युवाओं में लगातार बढ़ती नाराजगी के बीच आखिरकार सोहागपुर एरिया के महाप्रबंधक बी.के. जेना को स्वयं रामपुर पहुंचकर ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ घंटों तक मैराथन बैठक करनी पड़ी। इस दौरान ग्रामीणों ने एक-एक कर अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं और साफ शब्दों में कहा कि अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई चाहिए।जानकारी के अनुसार रामपुर क्षेत्र में संचालित परियोजनाओं और निजी कंपनियों के विस्तार के चलते लंबे समय से विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा सुलग रहा है। किसानों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीनें परियोजनाओं के नाम पर अधिग्रहित कर ली गईं, लेकिन बदले में उन्हें न तो स्थायी रोजगार मिला और न ही सम्मानजनक पुनर्वास। कई प्रभावित परिवार आज भी मुआवजा, नौकरी और मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

लगातार बढ़ते असंतोष ने पिछले कुछ दिनों में क्षेत्र का माहौल पूरी तरह गरमा दिया था।ग्रामीणों ने बैठक में सबसे ज्यादा नाराजगी स्थानीय युवाओं की उपेक्षा को लेकर जताई। लोगों का कहना था कि कंपनियों द्वारा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन नियुक्तियों में बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। जय अंबे कंपनी सहित अन्य निजी कंपनियों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्थानीय बेरोजगारों को नजरअंदाज कर क्षेत्र के बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जिससे युवाओं में भारी आक्रोश है।बैठक के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिला और विस्थापित परिवारों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि विकास कार्यों के नाम पर यदि उनके अधिकारों का हनन जारी रहा तो क्षेत्र में उग्र विरोध की स्थिति बन सकती है।महाप्रबंधक बी.के. जेना ने बैठक में ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि विस्थापन, पुनर्वास और रोजगार से जुड़े मामलों पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे और कंपनियों से चर्चा कर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि परिणाम चाहिए।बैठक में महाप्रबंधक संचालन मनीष श्रीवास्तव, उप क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप शर्मा सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि प्रबंधन क्षेत्र के विकास के साथ स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाएगा।वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश शर्मा ने बैठक में कहा कि विकास के नाम पर ग्रामीणों के अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता। यदि किसी परिवार की जमीन ली जाती है तो उसके परिवार को स्थायी रोजगार और बेहतर पुनर्वास मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी युवाओं को आंदोलन की ओर धकेल रही है और कंपनियों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी होगी।पूर्व एसडीएम एवं वरिष्ठ नेता ने भी बैठक में कहा कि प्रशासन और कंपनियों को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र में असंतोष विस्फोटक रूप ले सकता है। वहीं ग्राम पंचायत रामपुर के सरपंच, जनपद सदस्य एवं सभापति चंद्र कुमार तिवारी ने सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कंपनियों को सीएसआर मद से प्रभावित गांवों के विकास में भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।उप सरपंच, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शांति अतरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग दोहराई। बैठक में कई ग्रामीणों ने मुआवजा भुगतान में देरी और पुनर्वास स्थलों पर सुविधाओं की कमी की शिकायतें भी अधिकारियों के सामने रखीं। अधिकारियों ने सभी समस्याओं को नोट करते हुए समाधान का भरोसा दिलाया।बैठक के अंत में महाप्रबंधक बी.के. जेना ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं रहने दी जाएगी और ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच लगातार संवाद बनाए रखा जाएगा ताकि किसी भी विवाद को समय रहते सुलझाया जा सके।रामपुर में हुई यह बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लंबे समय बाद प्रबंधन के शीर्ष अधिकारी स्वयं ग्रामीणों के बीच पहुंचे और सीधे संवाद किया। हालांकि क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अब उनकी नजर केवल बैठकों और आश्वासनों पर नहीं बल्कि जमीन पर होने वाली कार्रवाई पर रहेगी। आने वाले दिनों में प्रबंधन क्या कदम उठाता है, इस पर पूरे क्षेत्र की निगाहें टिकी हुई हैं।

नगर में जगह जगह अवैध रूप से लगा दिए गए होर्डिंग एवं फ्लेक्स बोर्ड

हरिभूमि न्यूज कोतमा।

नगर में जगह जगह अवैध रूप से होर्डिंग एवं फ्लेक्स बोर्ड लगा दिए गए हैं जिसके कारण हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि तेज आंधी तूफान चलने के कारण लोहे के प्लेट में लगे फ्लेक्स एवं होडिंग उड़कर सड़क पर आ जाते हैं यहां तक की कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हो गई है। गुरुवार को दोपहर में तेज आंधी तूफान चलने के कारण स्टेशन चौक के पास दीनदयाल शॉपिंग कांप्लेक्स में लगे फ्लेक्स बोर्ड उड़कर सड़क पर आ गया गनीमत रही की किसी को चोट नहीं आई एक बड़ी दुर्घटना होते-होते टल गई। स्टेशन चौक गांधी चौक के साथ ही मुख्य सड़कों पर हर समय भीड़भाड़ बनी रहती है। गुरुवार को दोपहर मे अचानक आंधी तूफान के कारण स्टेशन चौक में जर्जर फ्लेक्स बोर्ड गिर गया जिससे एक महिला सब्जी विक्रेता बाल बाल बच गई यहां तक कि फ्लेक्स के पाईप के टुकड़े टुकड़े हो गए। नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन से नगर में लगे अवैध रूप से होर्डिंग एवं फ्लेक्स बोर्ड को अभियान चलाते हुए बीच बाजार लगे जर्जर और पुराने बोर्ड निकाले जाये, क्योंकि तेज आंधी तूफान में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है कि मांग की है।

बुढ़ार को सौगात: तहसील में जल्द शुरू होगा एसडीएम कोर्ट

शहडोल। क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी और बेहद राहत भरी खबर है। बुढ़ार तहसील में लंबे समय से लंबित अनुविभागीय कार्यालय और न्यायालय की स्थापना की मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। अधिवक्ता ओंकार प्रसाद गुप्ता द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए एक प्रभावी ज्ञापन के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। सबसे सुखद खबर यह है कि आगामी सोमवार से ही एसडीएम बुढ़ार में बैठकर कामकाज संभाल सकते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ही राजस्व और प्रशासनिक मामलों का त्वरित निपटारा हो सकेगा।

गौरतलब है कि बुढ़ार तहसील का गठन हुए 15 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। इसके दायरे में बुढ़ार, धनपुरी, बकहो नगर परिषद समेत लगभग 76 गांव आते हैं। विडंबना देखिए कि यहाँ जिला सत्र एवं अपर न्यायालय तो संचालित हैं, लेकिन अनुविभागीय कार्यालय और न्यायालय के लिए आज भी लोगों को 24 किलोमीटर दूर सोहागपुर दौडऩा पड़ता है। इस भौगोलिक दूरी के कारण पिछले कई दशकों से ग्रामीणों और नगरवासियों का समय और पैसा पानी की तरह बह रहा था। सोहागपुर में मुकदमों का बोझ बढऩे से आम

जनता हलाकान थी। इस गंभीर समस्या को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल तक भी पत्राचार किया गया था, जिसके बाद अब प्रशासन ने यह जनहितैषी कदम उठाया है।

सोमवार से बुढ़ार में ही एसडीएम के बैठने की सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिकों, ग्रामीणों और अधिवक्ता संघ में खुशी की लहर दौड़ गई है। तहसील कार्यालय के भीतर ही अनुविभागीय कोर्ट शुरू होने से न केवल कामकाज में पारदर्शिता आएगी, बल्कि दलालों और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। लगातार विकसित हो रहे बुढ़ार ब्लॉक को इस प्रशासनिक विस्तार से नई मजबूती मिलेगी। अब क्षेत्रवासियों को इंतजार है तो बस स्थायी न्यायालय भवन और पूर्णकालिक कार्यालय की विधिवत शुरुआत का, जिससे बुढ़ार के विकास को एक नई रफ्तार मिल सके।

बूंदा बांदी और गरज-चमक के साथ हुई बारिश, भीषण गर्मी व उमस से बड़ी राहत

हरिभूमि न्यूज कोतमा। कोतमा में गुरुवार और शुक्रवार की रात हुई बूंदाबांदी और गरज-चमक के साथ बारिश ने भीषण गर्मी व उमस से बड़ी राहत दी है। रात भर चले इस मौसम के बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से सुकून मिला है। नौतपा के पांचवें दिन लोगों ने राहत का अहसास किया। भीषण गर्मी के बाद इस बेमौसम बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से शानदार राहत दी है। दिन और रात के तापमान में गिरावट आने से रात में सुकून भरी नींद और दिन के समय धूप में कमी आई है। रात भर आसमान में बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। स्थानीय निवासियों के अनुसार, इस अचानक आई बारिश से किसानों को भी अपनी कृषि संबंधी तैयारियों में नमी का फायदा मिलने की उम्मीद है, जबकि आम जनता को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत मिली। गुरुवार शाम अचानक बदले मौसम ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। शाम को तेज हवा के साथ आसमान में घने बादल छा गए और गुरुवार शुक्रवार की रात करीब 3.00 बजे के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। रुक-रुक कर बारिश होती रही। कहीं तेज हवा के साथ बारिश हुई तो कहीं लगातार बूंदाबांदी का दौर चला। बारिश होने के कारण शुक्रवार को

तापमान तीन डिग्री तक गिर गया। अगले तीन दिन बारिश और बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम में बदलाव के कारण पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि इससे पहले मौसम विभाग ने हीटवेव के साथ तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया था। बारिश के बाद तापमान में करीब 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन दिनों तक रूक रूक कर बादल छाए रहने और बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं।

भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव पूरे श्रद्धा व उल्लास से मनाया गया

जगत के कल्याण के लिए भगवान का अवतरण होता हैं: महन्त अर्जुन दास

बुढार। पुण्य सलिला धारकुण्डी आश्रम अमरकंटक में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर श्रद्धालु धर्म प्रेमी अपना जीवन सौभाग्यमय बना रहे हैं।

अधिमास के पावन अवसर पर श्रीराम जानकी मन्दिर बुढार के पूज्य महन्त श्री अर्जुन दास जी महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की प्रेरणादायी कथा का श्रवण श्रद्धालुजनो को कराते हुए कहाकि-जगत के कल्याण के लिए ही भगवान का अवतरण होता है, और ईश्वरीय सृष्टि में प्रकृति के कुछ अटल नियम होते हैं, जिनसे ही सृष्टि क्रम चलता है, तथा मानव द्वारा जब इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तब सृष्टि क्रम में बाधा उत्पन्न हो जाती है,यह बाधा मानव के देहाभिमान, लोभ, मोह, मद, अनावश्यक प्रतिष्ठा को बलात प्राप्त करने की इच्छा, आसक्ति में बदल जाती है,तो मनुष्य के विचार व कर्म, मानव समाज के साथ, जीव-जगत व प्रकृति दोनों का शोषण होने लगता है, और अन्याय, दुराचार बढ़ जाते हैं, सज्जन, संत व गौमाता को पीड़ित होना पड़ता है, इसे भगवान सहन नहीं कर पाते हैं,तब भगवान का अवतरण, इन आसुरी वृत्तियों का विनाश करने के लिए होता है।

यह अवतरण भी उस घर में या उन माता-पिता के घर में होता है जो साधना, तपस्या व अपनी सज्जनता से जगत के कल्याण की भावना रखते हैं, त्याग व समर्पण उनके जीवन शैली में होता है।

महंत श्री अर्जुन दास जी महाराज ने प्रेरणादायी कथा में कहाकि-भगवान श्रीकृष्ण जी का अवतार कंस के अत्याचार, दुराचार व आसुरी वृत्ति इतनी बढ़ गई थी कि मानव समाज में मात्र नहीं, बल्कि अपने ही घर परिवार के सभी रिश्तों की मान्यता को समाप्त कर,दानवी वृत्तियों को स्थापित कर रहा था, तब भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण का अवतरण वसुदेव व देवकी के यहां, विषम परिस्थितियों में अवतरण हुआ। सज्जनों, संतों, पीड़ितों, देवी -देवताओं, गौमाता की रक्षा के लिए श्रीकृष्ण जी के अवतरण का विस्तार से महंत श्री महराज श्री ने आध्यात्मिक विश्लेषण करते हुए, अध्यात्म प्रेमियों को श्रीकृष्ण जन्म को आनन्द से, आनन्दित करायें और श्रद्धालुजन पूरे श्रद्धा भाव से झूम उठे।

श्रीराम जानकी मन्दिर भक्त परिवार बुढार के संयोजन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है जो आगामी 31 मई तक चलेगा।

40 घायल-कई की हालत गंभीर

तिवनी के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी

4 की मौत सनी धाम से लौट रहे 50 ग्रामीण हुए हादसे का शिकार

हरिभूमि बिरसिंहपुर पाली। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र मे शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 40 लोग घायल हो गये। हादसा उस समय हुआ, जब श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पडनिया के करीब 50 ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर बिजौरा मे पूजन कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अनूपपुर सीमा से लगे तिवनी गांव स्थित सनी धाम के पास अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रॉली में सवार कई लोग उसके नीचे दब गये और मौके पर ही 4 ग्रामीणों ने दम तोड़ दिया, ज दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। मौके पर पहुंचा पुलिस और प्रशासनघटना की सूचना मिलते ही पाली एसडीएम, पुलिस प्रशासन औरराजस्व अमला तत्काल मौके पर पहुंच गया। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस एवं य वाहनों की सहायता से पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि कई घायलों की हालत गंभीर ह उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

खबर संक्षेप

नौतपा में प्रकृति की नरमी

अमरकंटक। मध्यप्रदेश की पावन धार्मिक, आध्यात्मिक एवं पर्यटन नगरी अमरकंटक में इस वर्ष नौतपा का स्वरूप पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। जहां सामान्यतः नौतपा के दिनों में सूर्य की प्रचंड तपिश और भीषण गर्मी लोगों को बेहाल कर देती है, वहीं इस बार प्रकृति ने अपने सौम्य रूप से लोगों को राहत प्रदान की है। नौतपा के पांचवें दिन शुक्रवार को भी अमरकंटक का मौसम सुहावना बना रहा तथा अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते दो दिनों से अमरकंटक एवं आसपास के क्षेत्रों में रुक-रुक कर तेज हवाओं के साथ वर्षा का दौर जारी है। गुरुवार 28 मई को दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और शाम ढलते ही आकाश में घने बादलों का डेरा जम गया। रात्रि लगभग साढ़े आठ बजे से नौ बजे के बीच तेज आंधी-तूफान के साथ जोरदार वर्षा हुई, जिससे पूरा क्षेत्र कुछ समय के लिए अस्त-व्यस्त हो उठा। तेज हवाओं के प्रभाव से नगर के विभिन्न हिस्सों में कई पेड़ धराशायी हो गए। कल्याण आश्रम के सामने स्थित एक विशाल वृक्ष उखड़कर दीवार से जा टिका, जिससे आसपास के लोगों में कुछ देर के लिए भय का वातावरण बन गया। हालांकि सौभाग्यवश इस प्राकृतिक घटना में किसी प्रकार की जनहानि अथवा गंभीर दुर्घटना नहीं हुई। आंधी-तूफान का असर यातायात व्यवस्था पर भी दिखाई दिया। अमरकंटक से कबीर चबूतरा जाने वाला मार्ग रातभर बाधित रहा। मार्ग पर पेड़ गिर जाने के कारण आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया था। प्रशासन एवं स्थानीय नागरिकों के संयुक्त प्रयास से शुक्रवार प्रातः मार्ग को पुनः सुचारु कराया गया, जिसके बाद यात्रियों और श्रद्धालुओं को राहत मिली।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अनूपपुर रेलवे स्टेशन परिसर में निःशुल्क शीतल पेयजल किया गया वितरण

अनूपपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित के साथ-साथ समाज हेतु वशिष्ठ हित में कार्य करते आया है आज उसी क्रम में अनूपपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा इस बढ़ती भीषण गर्मी तप्ती, चिलचिलाती कड़ी धूप में दूर दराज से आए हुए रेलवे स्टेशन परिसर में बैठे सभी यात्रियों को निःशुल्क शीतल पेयजल वितरित किया गया, साथ ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि विद्यार्थी परिषद लगातार अनेकों प्रकार के सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता रखता है और इस भीषण गर्मी में अभी यह निशुल्क पेयजल वितरण कई दिनों तक चलाया जाएगा। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने समाज के लोगों से यह भी आग्रह किया है कि लोगों के साथ-साथ बेजुबान पक्षियों व में मवेशियों के लिए अपने घर के बाहर पानी की व्यवस्था जरूर करें ताकि वह पशु पक्षी भी अपनी प्यास बुझा सके। इस निशुल्क पेयजल व्यवस्था वितरण में प्रमुख रूप से जिला संगठन मंत्री शिवेंद्र चतुर्वेदी, लवकुश रौतेल, धीरेंद्र तिवारी, दीपक, गौरीशंकर, निशि, सिमरन, मयंक, विराग, आदित्य, साक्षी, अंकिता, आकाश, प्रिंस, अंकित, ऐश्वर्य, विवेक, रोहित आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

आईजीएनटीयू में छात्र की आवाज दबाने की साजिश पर उठते सवाल

आंदोलन से डरी व्यवस्था या सच से घबराया विश्वविद्यालय?

15 लाख का शोर, लेकिन छात्र के सवालों पर चुप क्यों विश्वविद्यालय?

भेदभाव, मानसिक प्रताड़ना और प्रशासनिक खेल के बीच न्याय मांगता आदिवासी छात्र

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय इन दिनों शिक्षा से ज्यादा विवादों का केंद्र बन चुका है। एक आदिवासी छात्र न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और कार्यपरिषद सदस्य अब पूरे मुद्दे को "वसूली" और "गुमराह" जैसे शब्दों में उलझाने में जुटे दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतने दिनों तक मौन रहने वाले जिम्मेदार चेहरे अचानक सक्रिय क्यों हुए है? क्या यह छात्र की आवाज दबाने और विभागाध्यक्ष को बचाने की रणनीति है? जैसे ये पूर्व से करते हुए आए है।किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान उसकी शिक्षा, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण व्यवस्था से होती है, लेकिन आईजीएनटीयू में इन दिनों जो तस्वीर सामने आ रही है, वह बेहद चिंताजनक है। एक आदिवासी विश्वविद्यालय का छात्र लगातार आरोप लगा रहा है कि विभागाध्यक्ष ने उसके साथ भेदभाव किया, उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई, इंटरनल परीक्षा की सूचना तक उससे छिपाई गई और विरोध करने पर उसे विभाग के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया गया। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद विश्वविद्यालय लंबे समय तक चुप बैठा रहा है। अब जब छात्र का आंदोलन जनसमर्थन लेने लगा, तब कार्यपरिषद सदस्य सामने आकर आंदोलन को "साजिश", "वसूली" और "समाज को गुमराह" करने वाला बताने लगे है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय रहते निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई? यदि छात्र गलत था तो कार्यवाही पहले क्यों नहीं हुई, और यदि सही था तो दोषियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? यही चुप्पी अब पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही है।

छात्र नहीं, व्यवस्था कटघरे में है

जिस मुद्दे को आज "शॉर्ट अटेंडेंस" कहकर छोटा दिखाने की कोशिश हो रही है, वही मामला अब विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल बन चुका है। छात्र का कहना है कि वह नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहता था, लेकिन उसकी अटेंडेंस दर्ज नहीं की गई। यदि यह आरोप सही है, तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित भेदभाव माना जाएगा। दुर्भाग्य यह है कि प्रशासन ने छात्र की शिकायत सुनने के बजाय पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया। अब जब आंदोलन ने जोर पकड़, तब अचानक "नियम" और "अनुशासन" की बातें की जा रही हैं। सवाल यही है कि क्या नियम केवल कमजोर छात्रों के लिए हैं?

आखिर इतने दिनों बाद क्यों जागे कार्यपरिषद सदस्य?

जब छात्र लगातार धरने पर बैठा था, मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव के आरोप लगा रहा था, तब विश्वविद्यालय और कार्यपरिषद के जिम्मेदार चेहरे खामोश थे। लेकिन जैसे ही मामला सार्वजनिक बहस का विषय बना, अचानक प्रेस नोट और आरोपों की बौछार शुरू हो गई। यह देरी कई सवाल पैदा करती है। क्या पहले मामले को दबाने की कोशिश हो रही थी? क्या विभागाध्यक्ष को बचाने के लिए रणनीति बनाई जा रही थी? यदि कार्यपरिषद सदस्य इतने गंभीर थे, तो

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
INDIRA GANDHI NATIONAL TRIBAL UNIVERSITY

उन्होंने पहले निष्पक्ष जांच की मांग क्यों नहीं उठाई? अब आंदोलन को "वसूली" बताकर असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश दिखाई दे रही है।

स्लीपर सेल" और "आतंकवादी" जैसे शब्दों से किसे डराया जा रहा?

इस पूरे विवाद का सबसे खतरनाक पहलू वह भाषा है, जिसका इस्तेमाल छात्र और आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल पीडीएफ और संदेशों में "स्लीपर सेल" और "आतंकवादी सोच" जैसे शब्दों का उपयोग किया गया। सवाल यह है कि क्या एक छात्र द्वारा न्याय मांगना अब विश्वविद्यालय में अपराध माना जाएगा? क्या असहमति जताने वालों को राष्ट्र विरोधी ठहराना नया प्रशासनिक हथियार बन चुका है? ऐसे शब्द न केवल छात्र की छवि खराब करते हैं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज की भावनाओं को भी आहत करते हैं। यह लोकतांत्रिक माहौल नहीं, बल्कि डर और दमन का संकेत देता है।

व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर करना प्रशासनिक कार्यवाही या प्रतिशोध?

छात्र का आरोप है कि उसे बिना कारण बताए विभाग के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया। यह वही मंच होता है जहां परीक्षा, इंटरनल और अकादमिक गतिविधियों की जानकारी साझा की जाती है। ऐसे में किसी छात्र को बाहर करना सीधे तौर पर उसकी शैक्षणिक पहुंच रोकने जैसा है। सबसे गंभीर आरोप यह भी है कि इंटरनल परीक्षा के समय में बदलाव की सूचना उसे नहीं दी गई। यदि ऐसा हुआ है, तो यह केवल तकनीकी गलती नहीं बल्कि छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस मुद्दे पर अब तक स्पष्ट जवाब देने से बचता नजर आ रहा है।

गलत हाथों में विश्वविद्यालय की कमान?

पूरे घटनाक्रम ने विश्वविद्यालय प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि एक छात्र को न्याय पाने के लिए आंदोलन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े और फिर भी प्रशासन केवल आरोपों की राजनीति करता नजर आए, तो यह किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए शर्मनाक स्थिति है। आदिवासी विश्वविद्यालय होने के बावजूद यदि आदिवासी छात्र खुद को असुरक्षित और प्रताड़ित महसूस करे, तो यह व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता मानी जाएगी। अब जरूरत केवल बयानबाजी की नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और छात्र के साथ हुए कथित भेदभाव की सच्चाई सामने लाने की है।

धूल का गुबार बना मुसीबत, एसईसीएल की सड़क से सांस लेना हुआ मुश्किल

सेमरा से केरहा मार्ग निर्माण में लापरवाही, अस्पताल-स्कूल तक प्रभावित

हरिभूमि न्यूज राजनगर। नगर परिषद बनगवां (राजनगर) क्षेत्र के अंतर्गत वेस्ट झिरिया खुली खदान (भलमुडी) के लिए सेमरा से केरहा मार्क तक बनाई जा रही सड़क अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही पर्यावरणीय नुकसान की शिकायतें सामने आने लगी थीं। वहीं अब सड़क पर डाले गए डस्ट और मिट्टी के कारण आसपास के रहवासी तथा राहगीर भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

लेवलिंग के लिए खोदे गए गड्ढे बने खतरा

सड़क निर्माण के दौरान लेवलिंग के लिए आसपास कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे खोद दिए गए। इन गड्ढों से निकाली गई मिट्टी का उपयोग सड़क निर्माण में किया गया। लेकिन कार्य पूरा होने के बाद भी गड्ढों को सुरक्षित नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गड्ढे अब हादसों का खतरा बने हुए हैं।

हवा में उड़ रहा डस्ट, घरों तक पहुंच रही धूल

सड़क निर्माण के कार्य में जो डस्ट डाल दी गई है। गर्मी और तेज हवाओं के कारण यह धूल लगातार उड़ रही है। जिससे आसपास के घरों, दुकानों और राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। राहगीरों की आंखों में धूल जा रही है तो वहीं लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है।

अस्पताल, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी भी प्रभावित

सबसे गंभीर बात यह है, कि इसी मार्ग पर अस्पताल, स्कूल और महाविद्यालय स्थित हैं। रोजाना हजारों लोग इस सड़क से गुजरते हैं। धूल के गुबार के कारण मरीजों, विद्यार्थियों और आम लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है, कि यदि सड़क पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाता तो धूल को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन ठेकेदार द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई।

स्थानीय लोगों में नाराजगी, कार्रवाई की मांग

क्षेत्र के रहवासियों ने एसईसीएल प्रबंधन और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल पानी का छिड़काव कराने और सड़क निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि कई दिनों से समस्या बनी हुई है। लेकिन प्रबंधन द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

पार्षद को झूठे केस में फंसाने की धमकी, कोतवाली में शिकायत

पार्षद संजय चौधरी का आरोप, अवैध कब्जे का विरोध करने पर रची गई साजिष

अनूपपुर। नगर पालिका अनूपपुर के वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद संजय चौधरी ने कोतवाली थाने में षिकायत दर्ज कराई है। पार्षद ने आरोप लगाया है कि एक महिला द्वारा उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पार्षद संजय चौधरी ने बताया कि रजनी रजक पति स्व. लाला रजक ने उनके विरूद्व जमीन दिलाने के नाम पर राषि लेने एवं धोखाधडी करने की षिकायत की है। पार्षद ने इस षिकायत को पूर्णतः असत्य, निराधार एवं तथ्यहीन बताया है। षिकायतकर्ता रजनी रजक द्वारा पूर्व में वार्ड क्रमांक-10 में अपने पुत्र के साथ मिलकर षासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण किया जा रहा था। उस समय उनके द्वारा निर्माण पर आपत्ति जताई गई थी और पूछा गया था कि किस आदेष एवं अनुमति से निर्माण हो रहा है। पार्षद का आरोप है कि आपत्ति जताने पर षिकायतकर्ता एवं परिवार के सदस्य उनसे विवाद एवं झगडा करने लगे। उन्हे धमकी दी गई कि वे कलेक्टर अनूपपुर से अनुमति लेकर निर्माण कर रहे है। इसके बाद पार्षद एवं वार्ड-10 के अन्य नागरिकों की षिकायत पर उक्त अवैध निर्माण कार्य को अधूरा छोड दिया गया था। संजय चौधरी ने

नगर पालिका परिषद अनूपपुर

षिकायत में कहा कि निर्माण रूकवाने से नाराज होकर षिकायतकर्ता के पुत्र राहुल रजक एवं पुत्री भारती रजक ने उन्हे जान से मारने की धमकी दी। यहां तक कि गाडी से कुचल देने की भी धमकी दी गई थी। पार्षद ने आगे बताया कि षिकायतकर्ता द्वारा वार्ड क्रमांक-02 में भी षासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसका उन्होने विरोध किया। पार्षद ने कहा कि उनका एकमात्र उददेष्य अपने वार्ड में अवैध गतिविधियों एवं कब्जों को रोकना है। पार्षद चौधरी ने अपनी षिकायत में कहा कि षिकायतकर्ता एवं उसके परिवार के सदस्य आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। षिकायतकर्ता का पुत्र आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है तथा वर्तमान में जेल में सजा काट रहा है। षिकायतकर्ता एवं उसकी पुत्री भारती रजक का व्यवहार भी इसी प्रकार का रहा है। पार्षद संजय चौधरी ने कहा कि उनके विरूद्व की गई षिकायत केवल दबाव बनाने, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने की नियत से की गई है। षिकायतकर्ता द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। उन्होने पुलिस से मांग की है कि झूठे एवं निराधार आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा साक्ष्य के अभाव में उनके विरूद्व कोई कार्यवाही न की जाए। साथ ही झूठी षिकायत कर छवि धूमिल करने वालों पर भी वैधानिक कार्यवाही की जाए। कोतवाली थाना पुलिस ने पार्षद की षिकायत प्राप्त कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।

ग्रामीणों की आय में वृद्धि

रोजगार के नए अवसर खोल रहा न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं टोरेंट पावर प्रोजेक्ट

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिले की रक्सा-कोलमी ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रस्तावित न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं उसकी सहायक कंपनी टोरेंट पावर की ऊर्जा परियोजना को ग्रामीण विकास और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि इस परियोजना से न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि ग्रामीणों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। परियोजना के चलते सड़क, परिवहन, निर्माण कार्य, छोटे व्यापार, होटल, किराना, मशीनरी और स्थानीय सेवाओं से जुड़े कई नए अवसर विकसित हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बड़े औद्योगिक निवेश से आसपास के गांवों में आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं और इसका सीधा लाभ स्थानीय परिवारों तक पहुंचता है। यही कारण है कि रक्सा-कोलमी क्षेत्र के अनेक ग्रामीण, व्यापारी और युवा इस परियोजना को क्षेत्र के भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि कुछ लोग विकास कार्यों को प्रभावित करने और माहौल भटकाने की कोशिशों में लगातार सक्रिय रहते हैं। क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों का कहना है कि ऐसे तत्व हर बड़ी परियोजना के समय अनावश्यक भ्रम की स्थिति बनाकर जिले में आने वाले निवेश और विकास की गति को प्रभावित करते हैं। वहीं कुछ लोग जबरन "विज्ञप्ति वीर" बनकर अनैतिक दबाव बनाने में लगे हुए हैं, जबकि वास्तविक आवश्यकता क्षेत्र में रोजगार, उद्योग और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की है। सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं नियमानुसार आगे बढ़ रही हैं तथा संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण भी जारी है। कंपनी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि परियोजना से जुड़े सभी कार्य वैधानिक प्रावधानों और पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस प्रकार की परियोजनाओं को सकारात्मक सहयोग मिलता है तो अनूपपुर जिला आने वाले समय में औद्योगिक और आर्थिक विकास का नया केंद्र बन सकता है। इससे न केवल क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि स्थानीय व्यापार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।

नर्मदा पुष्कर बांध बना मातम का साक्षी

18 घंटे बाद मिला सुरेश धुर्वे का शव, अमरकंटक शोक में डूबा

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक। पवित्र नगरी अमरकंटक स्थित नर्मदा पुष्कर बांध में गुरुवार को घटित दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध और शोकाकुल कर दिया। स्नान के दौरान गहरे पानी में समाए युवक सुरेश धुर्वे का शव लगभग 18 घंटे की कठिन खोजबीन और अथक प्रयासों के बाद शुक्रवार प्रातः करीब 8 बजे बाहर निकाला जा सका। इस हदयविदारक घटना के बाद बांध तट पर मातम पसरा रहा तथा परिजनों की चीख-पुकार ने उपस्थित लोगों की आंखें नम कर दीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार 28 मई को सुरेश धुर्वे नर्मदा पुष्कर बांध में स्नान करने पहुंचे थे। इसी दौरान वे अचानक गहरे पानी की ओर चले गए और देखते ही देखते लहरों में समा गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिक, पुलिस प्रशासन एवं बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचे और युवक की तलाश शुरू की गई। देर शाम तक लगातार खोजबीन जारी रही, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसी बीच मौसम ने भी राहत कार्य में बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी। तेज आंधी, तूफान और अतिवृष्टि के चलते रेस्क्यू अभियान को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। अनूपपुर जिला मुख्यालय से पहुंची पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम ने परिस्थितियां सामान्य होते ही शुक्रवार सुबह पुनः अभियान प्रारंभ किया। लगातार प्रयासों के बीच एसडीआरएफ टीम के साथ वार्ड क्रमांक 8 कपिला संगम निवासी साहसी युवक कृष्णा राठौर ने भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। लंबे समय तक चले संयुक्त प्रयासों के बाद सुरेश धुर्वे के शव को बाहर निकालने में सफलता मिली। शव बाहर आते ही परिजनों का विलाप सुनकर वातावरण गमगीन हो उठा और उपस्थित लोगों की आंखें भर आईं। पुलिस थाना अमरकंटक द्वारा मौके पर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग क्रमांक 0/26 कायम कर धारा 194 बीएनएसएस के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी है। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में गहरा आक्रोश और चिंता व्याप्त है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नर्मदा पुष्कर बांध जैसे गहरे जल क्षेत्रों में सुरक्षा के पर्याप्त और स्थायी इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। नागरिकों का कहना है कि पुष्कर बांध तट पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है। इससे पूर्व भी यहां कई हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से बांध क्षेत्र में मजबूत सुरक्षा दीवार, चेतावनी संकेतक, बैरिकेडिंग तथा प्रशिक्षित बचाव दल की स्थायी व्यवस्था किए जाने की मांग प्रशासन से की है।